

आयकर आयुक्त, पंचकुला बनाम 75 आईएम/एस हरियाणा राज्य सहयोग आपूर्ति और मार्केटिंग फेडरेशन लि. (आदर्श कुमार गोयल, जे.)

**आदर्श कुमार गोयल और अजय कुमार मित्तल के समक्ष**

आयकर आयुक्त,  
पंचकुला, - अपीलकर्ता

मैसर्स हरियाणा स्टेट को-ऑपरेशन सप्लाइ एंड  
मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड-प्रतिवादी

इटानो. 2004 का 112

26 अप्रैल, 2011

आयकर अधिनियम, 1961—एस. 80पी(2)(ए) (हाय), 80पी(2)(ई), 260ए, 263 - निर्धारित सहकारी समितियों का एक संघ है और अपने सदस्यों की कृषि उपज के विपणन में लगा हुआ है - धारा 80पी(2) के तहत छूट का दावा किया गया है। (ए)(iii) अधिनियम के तहत प्राप्त आय के संबंध में - निर्धारण अधिकारी ने छूट की अनुमति नहीं दी - रिमांड मामले पर निर्धारित के पक्ष में नए सिरे से निर्णय लिया - धारा 263 के तहत अपील में आयुक्त ने मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया - निर्धारित ने दायर किया अपील और ट्रिब्यूनल ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया - राजस्व अपील की अनुमति दी गई।

माना गया कि धारा 80पी(2)(ई) के तहत कटौती केवल भंडारण के लिए किराए पर देने से होने वाली आय के संबंध में उपलब्ध है और यदि निर्धारित ने भंडारण का उपयोग केवल विपणन के लिए किया है, तो कटौती की अनुमति नहीं है।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह माना गया कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और राजस्व के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण था, जो अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों के आह्वान को उचित ठहराता है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उठाए गए प्रश्नों का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया जाता है।

(पैरा 6)

योगेश पुटनी, अपीलकर्ता के वरिष्ठ स्थायी वकील।

आदर्श कुमार गोयल, जे. (मौखिक)

(1) यह अपील आयकर अधिनियम की धारा 260ए के तहत निर्धारित द्वारा प्रस्तुत की गई है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2003 के विरुद्ध 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") □

बेंच \*ए\*. चंडीगढ़ इटानो में। 520/चंडी/98. निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए, कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए:-

(i) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, प्रमुख आईटीएटी को आयकर आयुक्त के आदेश को धारा 263 के तहत रद्द करना उचित है, यह मानते हुए कि मूल्यांकन अधिकारी का आदेश गलत नहीं था और यह प्रतिकूल नहीं था राजस्व का ब्याज?

(11) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, विद्वान आईटीएटी का आयकर आयुक्त के आदेश को धारा 263 के तहत रद्द करना उचित है, जिसमें उन्होंने मूल्यांकन अधिकारी की कार्रवाई को कानून में अस्थिर माना था?

(2) करदाता सहकारी समितियों का एक संघ है और अपने सदस्यों की कृषि उपज के विपणन में लगा हुआ है। इसने अपने सदस्यों की उपज के विपणन से प्राप्त आय के संबंध में अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(iii) के तहत छूट का दावा किया। मूल्यांकन अधिकारी ने छूट को अस्वीकार कर दिया लेकिन रिमांड के बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 80पी(2)(ई) के तहत दावे की अनुमति दी, जिसे आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आय व्यवसाय से प्राप्त हुई थी और भंडारण स्थान को छोड़ देने से नहीं। ऐसा देखा गया :-

"निर्धारित को किया गया भुगतान वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए भंडारण, प्रसंस्करण के लिए परिसर को किराए पर देने के लिए नहीं है। बल्कि पैसा उस कीमत के एक घटक के रूप में प्राप्त किया जाता है जिस पर निर्धारित द्वारा अनाज की आपूर्ति की जाती है। तदनुसार मेरी राय है, निर्धारित का मामला हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के मामले से अलग है, जिसका उल्लेख निर्धारित ने किया है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ए.0. का आदेश गलत था।"

(3) करदाता की ट्रिब्यूनल में अपील पर, आयुक्त के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि निर्धारण अधिकारी के आदेश को राजस्व के हित के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। ऐसा देखा गया :-

"इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। निर्धारित धारा 80पी(2)(e) के तहत ऐसी कटौती का हकदार था। वास्तव में दूसरों से प्राप्त 57,88,204 रुपये की भंडारण शुल्क के संबंध में ऐसी कटौती का दावा किया गया था और पूरा करने के समय अनुमति दी

THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PANCHKULA v. #  
M/S HARYANA STATE CO-OPERATION SUPPLY AND MARKETING FEDERATION LTD. (सीआईटी) बिरौली राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 210 आईटीआर 906 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से भी समर्थित है। जहां यह माना गया है कि केवल विपणन की सुविधा के लिए गोदामों या गोदामों को किराये पर देने से प्राप्त आय वस्तुएं कटौती के लिए योग्य हैं। यानी I TAT, दिल्ली बेंच ने हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाम DOIT, 611TD 420 के मामले में जैसे का तैसा फैसला सुनाया। यहां तक कि उड़ीसा राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग बनाम सीआईटी 237 आईटीआर 589 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि निर्धारित गोदामों और गोदामों को किराये पर देने से प्राप्त आय के संबंध में कटौती का हकदार है। हम यह भी देखते हैं कि निर्धारित की कुल आय। जैसा कि मूल आदेश में निर्धारित किया गया था रु. 11,31,84,636. इस प्रकार एओ ने पूरी आय के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने धारा 80पी(2)(सी) के तहत कटौती को केवल गोदामों और गोदामों को किराये पर देने के लिए प्राप्त भंडारण शुल्क के माध्यम से आय के संबंध में प्रतिबंधित कर दिया था। ये तथ्य दर्शाते हैं कि एओ ने गलत तथ्यों या कानून के गलत प्रयोग से मामले का फैसला नहीं किया है। इसलिए, एओ द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं माना जा सकता है अन्यथा एओ द्वारा पारित आदेश को राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि सीआईटी एओ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, हम कर सकते हैं आगे बताते हैं कि यह सरकारी उपक्रम का मामला है। निर्धारित ने गेहूँ की खरीद की थी और एफसीआई और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न सेवाएं प्रदान की थीं, एफसीआई से प्राप्त राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसमें न केवल समर्थन मूल्य बल्कि मंडी शुल्क जैसे कई अन्य शुल्क भी शामिल थे। मंडी श्रम शुल्क, आंतरिक संचलन, भंडारण शुल्क, स्थापना शुल्क, ब्याज शुल्क आदि। इस प्रकार, निर्धारित ने न केवल गेहूँ खरीदा था बल्कि कई अन्य सेवाएं भी प्रदान की थीं। इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि निर्धारित के पास गोदाम और गोदाम थे जहां खरीदा गया गेहूँ संग्रहीत किया गया था। इतनी बड़ी रकम का भंडारण शुल्क रु. भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अपने गोदामों से 5.87 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। अगर एफसीआई का अपना होता गोदामों में सरकार ने ऐसे भंडारण शुल्क का भुगतान नहीं किया होगा। सहकारी समितियों द्वारा गोदामों और गोदामों को किराये पर देने से प्राप्त आय के संबंध में कटौती प्रदान करने का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना है। इस मामले में सहकारी समितियों को ऐसी आय के संबंध में ऐसी कटौती प्रदान करने का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो गया है। यह राजस्व का मामला नहीं है कि एओ ने मामले के प्रासंगिक पहलुओं की जांच किए बिना अनुचित जल्दबाजी में आदेश पारित किया था। इसके अलावा, निर्धारित का दावा ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों द्वारा भी समर्थित है। राजस्व ने एक भी ऐसे मामले का नेतृत्व नहीं किया है जहां कटौती के लिए इस तरह के दावे को स्वीकार्य नहीं माना गया है, इस प्रकार ऐसी आय धारा 80पी (2) (ई) के तहत कटौती के लिए योग्य है और एओ ने उचित दिमाग लगाने के बाद इसकी अनुमति दी है। उचित पूछताछ कर रहे हैं। इन तथ्यों के आलोक में हमें एओ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती। एओ ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों, सबूतों और सामग्री के आधार पर उचित दृष्टिकोण अपनाया, इसलिए, ऐसे आदेश को राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि धारा 263 के तहत क्षेत्राधिकार मानने से जुड़ी दो शर्तें यानी (i) आदेश गलत होना चाहिए और (ii) यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होना चाहिए, इस मामले में संतुष्ट नहीं हैं। तदनुसार, हम मानते हैं कि धारा 263 के तहत एओ के आदेश को संशोधित करना सीआईटी के लिए उचित नहीं था। हम धारा 263 के तहत पारित सीआईटी के आदेश को रद्द करते हैं और अपील के संबंधित आधारों की अनुमति देते हैं।"

(4) हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने 2005 के आईटीए नंबर 157 में इस न्यायालय के 8 सितंबर, 2010 के आदेश पर भरोसा किया, आयकर आयुक्त, पंचकुला बनाम मैसर्स हरियाणा राज्य सहकारी। सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, पंचकुला का मानना है कि धारा 80पी(2)(ई) के तहत कटौती केवल भंडारण के लिए किराए पर देने से होने वाली आय के संबंध में उपलब्ध है और यदि निर्धारित ने भंडारण का उपयोग केवल विपणन के लिए किया है तो कटौती की अनुमति नहीं है। उसमें टिप्पणियाँ हैं:-

"वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि निर्धारित माल खरीद रहा था और फिर एफसीआई को माल बेच रहा था और ऐसी स्थिति में, भंडारण निर्धारित के व्यवसाय का हिस्सा था और भंडारण क्षमता को किराए पर देने के समान नहीं था। तक□

हरि सिंह एवं अन्य आर. जे. एस. वंत सिंह  
(रानी चंद गुप्ता. जे.)

माल FC1 को बेचा गया। माल निर्धारित का था न कि एफसीआई का। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, मामला पूरी तरह से सूरत वेंकरसहकारी संघ और वेंटाका सुब्बाराव मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कवर होता है, जैसा कि उदयपुर सहकारी उपभोक्ता मामले में दोहराया गया है। भंडारण के लिए निर्धारित की आय को किराया शुल्क के बराबर नहीं माना जा सकता है।

(6) हमने पाया कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है वह पूरी तरह से लागू है। तदनुसार, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था जो अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों के आह्वान को उचित ठहराता था। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उठाए गए प्रश्नों का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

जे. ठाकुर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा